कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत में गिरावट

1024. **श्री राम जेठमलानी :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कपड़ा उद्योग के पर्याप्त विस्तार तथा विकास के बावजूद कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत में लगातार गिरावट आ रही है ;

(ख) यदि हां, तो 80 और 90 के दशकों के आरम्भ के दौरान देश में कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत कितनी रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में विद्यमान जलवायु को देखते हुए कपास के कपड़े का गैर-कपास के कपड़े की अपेक्षा अधिक उपयोग होता है ; और

(घ) यदि हां, तो कपास के कपड़े की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं। कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 1988 तक निरन्तर बढ़ रही थी। तथापि, वर्ष 1989 और 1990 में इसमें मामूली गिरावट आई।

(ख) 1980 और 1990 के दशकों के आरम्भ में देश में प्रति व्यक्ति खपत क्रमशः 13.43 मीटर तथा 14.03 मीटर थी।

(ग) सूती कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत ब्लेंडिड और गैर-सूती कपड़े की खपत से बहुत अधिक है।

(घ) कपड़े की कीमतें जिनमें सूती कपड़ा भी शामिल है, उत्पादन की लागत, लाभांश, मांग-पूर्ति स्थिति आदि जैसे बाजार संबंधी विभिन्न कारकों द्वारा तय की जाती है। तथापि, सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लाभार्थ जनता कपड़ा योजना, कन्ट्रोल कपड़ा योजना, सुलभ/सुषमन/सौभाग्य साड़ी योजना जैसी विभिन्न योजनायें क्रियान्वित कर रही है।

हथकरघा उद्योग में पूंजी निवेश

1025. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रि-मंडलीय उप समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि हथकरघा उद्योग को पूंजी प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाया जाना चाहिये और इस उद्योग में अधिक पूंजी निवेश के लिये सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हथकरघा उद्योग में अधिक पूंजी निवेश के लिये सुविधायें प्रदान करने संबंधी प्रश्न पर विचार किया है : और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की विस्तृत योजनायें क्या हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) हथकरघा क्षेत्र से संबंधित मामलों के लिये गठित अन्तर मंत्रालय समिति ने हथकरघी को पूंजी उपलब्ध कराने के मामलों की जांच की है।